

31/7/2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भाग 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय की पेश किया कि सरहद मौजा करावड़ी के पुराने खसरा नम्बर 398 रकाव 10 बीघा किरम बाराणी दोयम प्रार्थीगण के दादा रामाजी पुत्र उम्मेदाजी की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि से करावड़ी से नवसृजित ग्राम मालियों का मालियों के नवीन खसरा नम्बर 551 रकाव 0.03 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 552 रकाव 1.59 हेक्टर कुल रकाव 1.62 हेक्टर सृजित हुए। रामाजी के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 24.01.1967 से रामाजी के पुत्रों रायचंद, हेमासम, हुकमासम एवं प्रार्थीगण के पिता प्रेमारासम के नाम स्वीकृत हुआ। प्रार्थीगण के पिता का उक्त भूमि में हिस्सा 1/4 दर्ज था, हेमासम व हुकमासम ने मिलकर उनके पिता की सहमति के बिना सम्पूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 16.03.1970 का कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 08.08.1974 को स्वीकृत हुआ। उक्त बेचान प्रार्थीगण के पिता प्रेमारासम की बिना सहमति, हस्ताक्षर, एवं प्रतिफल प्राप्त किए किया गया, जो उक्त गलत है एवं काविले दुरस्त है। उक्त भूमि हमारे पुरस्नेनी खेतों से सटी हुई है एवं हमारा कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में खसरा के इन्द्राज का लाभ उठाते हुए बेचान करने एवं हमें भूमि से बेदखल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की विरुद्ध प्रार्थीगण फरमाई जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथार्थिति ताकैसला वाद बनाए रखें।

इस पर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब पेश किया कि प्रार्थी ने करीबन 54 वर्ष पश्चात् दावा पेश किया है, जो म्याद अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 50 एवं 110 के अनुसार भीतर तय म्याद प्रस्तुत नहीं करने से दावा/प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से खारिज है। मौके पर तारीख खरीद से आज दिन तक अप्रार्थीगण का कब्जा—काश्त है, जो प्रार्थीगण के पूर्ण जानकारी में था, अतः प्रार्थना पत्र काविले खारिज है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा हिन्दू परिवार के जायज आवश्यकता हेतु हिन्दू कर्ता खानदान द्वारा विक्रय किया गया, जो विक्रय पत्र में स्पष्ट तथ्यों का उल्लेख कर दिया है। हिन्दू कर्ता खानदान की हैसियत से अप्रार्थीगण को हिन्दू कर्ता खानदान की हैसियत से विक्रय का पूर्ण अधिकार था, अतः प्रार्थना पत्र काविले खारिज है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी थी और रायचंद, हेमा व हुकमा तीनों रामु के संयुक्त परिवार के हिन्दू कर्ता थे, जिन्होंने परिवार की जायज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेचान किया। बेचान दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज योग्य है। प्रार्थीगण के संयुक्त परिवार के खाते ममें मौजा करावड़ी के पुराने खसरा नम्बर 398 रकाव 10 बीघा भूमि व अन्य खसरा नम्बर रामा वल्द उम्मेदा की अविभक्त कुटुम्बकी सम्पति के रूप में अवस्थित थी, जिसमें से मौजा करावड़ी के नवीन सृजित राजस्व ग्राम मालियों की ढाणी के नवीन खसरा नम्बर 576, 566, 572, 1077/644, 520, 521, 567, 568, 643 की आराजी बंटवाड़े में दे दी थी, अतः उक्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक—हकूक अधिकार एवं कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। प्रार्थीगण के पिता प्रेमा ने अपने जीवनकाल में बेचाननामा दिनांक 04.03.1970 को चुनौती नहीं दी। अप्रार्थीगण प्रेमा के जीवनकाल से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है।



सहायक कर्ता, संचालक
संयुक्त

वाद में प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के भाईयों एवं उसके उत्तराधिकारियों को पक्षकार संयोजित नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण ने भूमि खरीद कर उसके विकास में काफी धनराशि खर्च की गई है। एवं वादग्रस्त भूमि में रहवासी ढाणी में परिवार सहित निवास कर रहे हैं। हिन्दू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के प्रावधान के प्रावधान उक्त संव्यवहार पर लागू है, अतः वादी के पिता की सहमति से किया गया बेचान दस्तावेज विधिसम्मत है। वर्तमान में जमीन की किमतों में भारी वृद्धि होने से प्रार्थीगण की नियत में खोट आने के कारण उक्त दावा/प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग-परेशान करने हेतु किया गया है। सन 1992 के आस-पास सांचौर तहसील में द्वितीय-भू-प्रबंध की कार्यवाही के दौरान मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग के आधार पर पर्चा लगान अप्रार्थीगण के नाम जारी कर आपत्तियों आमंत्रित की गई। प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से अप्रार्थीगण के नाम भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। अप्रार्थीगण पिछले 54 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा-काश्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है और प्रार्थीगण द्वारा म्याद माफी का प्रार्थना पत्र दावे के साथ पेश नहीं किया। इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थीगण 01 ता 03 क निरन्तर कब्जा-काश्त में होने व रिकॉर्डड खातेदार होने से प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हक-हकूक नहीं है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार, आधारहीन, मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पत्ति नहीं थी और तीन व्यक्ति कर्त्ता खानदान नहीं हो सकते हैं। प्रार्थीगण के पिता प्रेमा व बेचानकर्त्ता उनके पिता के निधन से पूर्व अलग-अलग रहवास करते थे। वादग्रस्त भूमि के बेचाननामा पर प्रार्थीगण के पिता के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान, सहमति नहीं होने से बेचाननामा उनके प्रति म्याद का प्रश्न लागू नहीं होता है। अतः 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण के कब्जा-काश्त में है और अप्रार्थीगण उसके किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

बहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। और बहस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थायी व्यादेश से संबंधित तीन निम्नलिखित सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना समुचित समझते हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामला:- प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थना में जमाबंदी खतौनी बदोबस्त प्रस्तुत की है, जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के दादा रामा वल्द उम्मेदाजी लगातार खातेदारी में दर्ज थी, एवं उनके दादा रामाजी के देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण के पिता प्रेमराम व उनके भाईयों रायचंद, हुकमा व हेमा के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम जरिए बेचाननामा दर्ज हुई। वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों व हक-हकूकों का निर्धारण मूल वाद में वाद जवाब तनकियात कायम पर साक्ष्य सवूतों के आधार पर ही संभव है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है, जो उनके दादा व पिता के नाम खातेदारी में दर्ज रही है, अतः यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निपेधाजा से पाबन्द नहीं किया जाता है, तो वाद में अनावश्यक जटिलताएं पैदा होंगी एवं वाद बहुलता बढ़ेगी, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सावित है।
2. सुविधा का संतुलन:- वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(संगठन अधिकारी, सांचौर)




आराजी रही है एवं प्रथम दृष्टया उनके पूर्वजों द्वारा किसी प्रकार का बैचान करना साबित नहीं होता है, परन्तु अप्रार्थीगण वर्तमान रिकार्डेड खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं है।


3. अपूर्णीय क्षति:— वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं जाती है, तो वादग्रस्त आराजी के दुर्व्यय से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे वाद बहुलता व अन्य कानूनी पेचीदगियां बढ़ेंगी, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह निनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में मूल वाद के निर्णयन तक वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके स्थिति में परिवर्तन नहीं किए जाने बाबत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसम्मत एवं उचित समझते हैं।

—:क्रियात्क आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा मालिया का गोलीया के खसरा नम्बर 551 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 552 रकबा 1.59 हैक्टर जुमले रकबा 1.62 हैक्टर के संबंध में ताफैसला वाद वर्तमान भू-अभिलेखीय राजस्व रैकर्ड एवं मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। न ही ऐसा अपने किसी प्रतिनिधि या नौकर द्वारा करावे। किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण, मरम्मत प्लांटिंग, चारदीवारी आदि नहीं करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम हो। बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर, साँचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साँचौर)


सहायक कलेक्टर, साँचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साँचौर)

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को को सर इजलास सुनाया गया।